

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य

बनाम

अमर देव प्रभा एवं अन्य

(2020 की सिविल अपील संख्या 2197)

18 मार्च, 2020

[एस. ए. बोबडे, सी जे. बी. आर. गवई और सूर्य कांत, जे.जे.]

निविदाएं - अपीलकर्ता बीसीसीएल द्वारा 'ओबी को हटाने, अग्निशमन के साथ कोयले के निष्कर्षण और परिवहन के लिए एचईएमएम को किराए पर लेने' के प्रयोजनों के लिए निविदा आमंत्रित करने वाला एक नोटिस जारी किया गया था - अपीलकर्ता का उद्देश्य ठेका फर्म था जिसने निविदा कार्य को पूरा करने के लिए सबसे कम लागत अनुमान की पेशकश की थी - बोली ऑनलाइन आयोजित करने के लिए कहा गया था - जब नीलामी आगे बढ़ी, कनेक्टिविटी की समस्याएं थीं जिसके कारण बोलियां जमा करने में विफलता हुई - अंतराल में, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दोपहर 12:33 बजे की गई 2345 करोड़ रुपये की अंतिम बोली तीस मिनट तक अनुत्तरित रही और नीलामी स्वचालित रूप से दोपहर 1:03 बजे बंद हो गई - प्रतिवादी नंबर 1 को सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया - हालांकि, तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, नीलामी को दोपहर 2.30 बजे फिर से शुरू किया गया और सभी बोलीदाताओं को सूचित किया गया - तदनुसार, प्रतिवादी नंबर 1 सहित कई प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न बोलियां प्राप्त हुईं - नीलामी 1 घंटे और 27 मिनट के विस्तारित समय के लिए आगे बढ़ी - एलओए सफल बोलीदाता को जारी किया गया था, यानी प्रतिवादी नंबर 6 - प्रतिवादी नंबर 1 ने यह घोषित करने के लिए रिट याचिका दायर की कि यह सफल बोलीदाता था और प्रतिवादी नंबर 6 को जारी एल ओ ए को रद्द करने के लिए - यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता की ओर से चूक हुई थी - एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया - हालांकि, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने माना कि प्रक्रियात्मक खामियां थीं और अपीलकर्ता द्वारा जारी एल ओ ए को रद्द कर दिया और

नीलामी के पुनः संचालन का नीलामी प्रक्रिया के बारे में - नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने से पहले, यह स्पष्ट है कि सभी बोलीदाताओं को संदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्रक्रिया को दोपहर 1:03 बजे नीलामी बंद होने और 2.30 बजे फिर से शुरू होने के बीच की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की कोई संभावना नहीं थी - नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के कुछ मिनटों बाद, बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं - इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ का आक्षेपित आदेश अपने निष्कर्ष में सही नहीं है कि अपीलकर्ता की ओर से पर्याप्त प्रक्रियात्मक खामियां थीं - परिणामस्वरूप, खण्ड न्यायपीठ के निर्णय को निरस्त किया जाता है।

अपीलों का निपटान करते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया: रिट याचिका की विचारणीयता

1. निविदाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे का गहराई से पता लगाया गया है। यह तय है कि संवैधानिक अदालतें केवल किसी निर्णय की वैधता से संबंधित हैं, न कि इसकी ध्वनि से। अलग तरह से कहें तो अदालतों को कार्यकारी अधिकारियों या तंत्रों के फैसलों पर अपील में नहीं बैठना चाहिए। प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है, और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में राज्य को अक्षांश दिया जाना चाहिए ताकि शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण का अतिक्रमण न हो। हालांकि, अवैधता, तर्कहीनता और प्रक्रियात्मक अनौचित्य के आरोप अदालतों के लिए अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने और ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए पर्याप्त आधार होंगे। यह हमारी अनूठी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से सच है, जिसने कई बार न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता का प्रदर्शन किया है। इसलिए, यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी जो न्यायिक जांच का विषय होगी, न कि अंतिम परिणाम (पूर्व के निर्धारण को निर्देशित करने के लिए आवश्यक को छोड़कर)। [अनुच्छेद 29] [616- सी ई]

2. ऐसे मामलों में जहां एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है, रिट आमतौर पर उचित उपाय होगा। निविदा मामलों में, ऐसा तब हो सकता है जब कोई पार्टी राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य के लिए पकड़ना चाहती है या

इसे मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है; या जब कार्यकारी कार्यों या विधायी साधनों को व्यापार और वाणिज्य पर ले जाने की स्वतंत्रता के उल्लंघन में होने के लिए चुनौती दी जाती है। हालांकि, रिट अस्वीकार्य हैं जब आरोप पूरी तरह से एक संविदात्मक अधिकार या कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में हैं। इसलिए, रिट राहत मांगने वाले व्यक्तियों को भी न्यायालय को सक्रिय रूप से संतुष्ट करना चाहिए कि वह जो अधिकार मांग रहा है वह सार्वजनिक कानून में एक है, न कि केवल संविदात्मक है। ऐसा करने में, वाणिज्यिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और मिलीभगत, अवैधता और सार्वजनिक संसाधनों की फिजूलखर्ची की वास्तविक संभावना के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है। [अनुच्छेद 32] [617-सी-ई]

3. वर्तमान मामले में, हालांकि यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ न्यायिक समीक्षा के दायरे के आसपास के इन सिद्धांतों से अवगत थी, हालांकि, यह प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या बड़े सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे थे। इसके विपरीत, इस न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी नंबर 1 का हित विशुद्ध रूप से निजी और मौद्रिक प्रकृति का था। [अनुच्छेद 36] [618-जी]

4. पहला प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि वह किस सार्वजनिक कानून के अधिकार का दावा कर रहा था। ए एम आर-देव प्रभा के मामले का मुख्य जोर इस तथ्य पर रहा है कि 05.05.2015 को दोपहर 1:03 बजे इसे सबसे कम बोलीदाता (या एल-1) घोषित किया गया था। तथापि, एल-1 बोलीदाता घोषित किए जाने से किसी भी संस्था को ठेका देने के लिए सार्वजनिक कानून का अधिकार नहीं मिलता है। [अनुच्छेद 40][620-सी]

नीलामी प्रक्रिया में कमियां

5. केंद्रीय सतर्कता आयोग ("सीवीसी") की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट का लाभ उठाते हुए, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 दोनों ने अपनी क्षमताओं के अनुसार सदाशयी तरीके से काम किया। भले ही यह सच है कि बीसीसीएल अधिक जिम्मेदारी ग्रहण कर सकता था और सी1-इंडिया इंटरनेट मुद्दों की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता था, फिर भी सुधार की संभावना प्राधिकरण की कार्रवाई को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अवैध परितोषण

द्वारा उच्चारण किए जा रहे निर्णयों का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, या अन्यथा धोखाधड़ी या क़ानून के विपरीत या तो स्पष्ट रूप से बनाया गया है या स्थापित नहीं किया गया है। [अनुच्छेद 44] [621-ई जी]

6. यह न्यायालय सीमित बैंडविड्थ की तकनीकी समस्याओं के अस्तित्व में उद्यम करने के लिए आवश्यक नहीं समझता है। वही तथ्य का प्रश्न है। तथापि, दूसरे आईईएम, सीईआरटी-इन, टीसीएल के साथ-साथ सीवीसी के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि खंडपीठ ने यह निर्णय देने में गलती की कि कोई तकनीकी कठिनाइयां नहीं थीं। इसके अलावा, ऐसा निष्कर्ष बाद की घटनाओं के साथ है। इंटरनेट की कोई समस्या नहीं होने का मतलब है कि किसी अन्य बोलीदाता ने दोपहर 12:33 बजे प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पेश की गई 2345 करोड़ रुपये की बोली का मुकाबला करना उचित नहीं समझा और यह प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित सबसे कम कीमत थी। हालांकि, यह स्पष्ट है कि नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के मिनटों में बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं, जिसमें 2043 करोड़ रुपये की अंतिम बोली शाम 7:27 बजे नीलामी बंद होने से कुछ सेकंड पहले ही लगाई गई थी। [अनुच्छेद 46] [622-एच; 623-ए-बी]

7. समय विस्तार की मात्रा से संबंधित प्रश्नों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि सी आई-इंडिया द्वारा सभी को एक ही संदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्रक्रिया को दोपहर 1:03 बजे नीलामी बंद होने और दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू करने के बीच की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा। इस तरह के समान संचार ने न केवल सभी बोलीदाताओं को एक समान पायदान पर रखा, बल्कि ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की कोई संभावना नहीं थी। जब यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है कि उन्होंने सोचा था कि नीलामी शाम 7:35 बजे बंद हो जाएगी और इसलिए उन्हें जल्दी बंद होने पर आश्चर्य हुआ, और न ही उन्होंने वास्तव में फिर से शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की व्याख्या पर प्रकाश डाला या आपत्ति जताई, सवाल विवादास्पद है और इस पर एक निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए। [अनुच्छेद 49] [623-जी; 624-ए-बी]

प्राधिकरण की व्याख्या का सम्मान

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

8. अंत में, यह न्यायालय एक अन्य मूलभूत समस्या से निपटने के लिए आवश्यक मानता है। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 केवल एन आई टी की शर्तों को लागू करना चाहता है। इस तरह के अभ्यास में निहित संविदात्मक शर्तों की व्याख्या है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुबंधों की न्यायिक व्याख्या विधियों की व्याख्या करते समय एक अलग पायदान पर है। [अनुच्छेद 51] [624-डी-ई]

9. वर्तमान तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि बीसीसीएल और सी1-इंडिया ने एनआईटी के खंडों का सहारा लिया है, चाहे वह प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में प्रतिवादी नंबर 6 की देरी या तकनीकी विफलता के आधार पर नीलामी फिर से शुरू करने के उनके निर्णय को उचित ठहराने के लिए एबीसीडी ई एफ जी एच 607 को सही ठहराना हो। बीसीसीएल ने इन दस्तावेजों को लिखने के बाद, उनकी आवश्यकताओं की सराहना करने और उनकी व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में है। [अनुच्छेद 52] [624-ई-एफ]

10. उच्च न्यायालय को इस समझ को स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विकृत या दुर्भावनापूर्ण न हो। यह देखते हुए कि इन खंडों की बीसीसीएल की व्याख्या कैसे प्रशंसनीय थी और बेतुकी नहीं थी, केवल संविदात्मक व्याख्या की राय में मतभेद उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने का आधार नहीं होना चाहिए था कि अपीलकर्ता ने अवैधता की है। [अनुच्छेद 53][624-एफ-जी]

जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य (2007) 14 एससीसी 517: [2006] 10 सप्ल. एस सी आर 606; मां बिंदा एक्सप्रेस कैरियर बनाम नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (2014) 3 एससीसी 760: [2013] 12 एससीआर 529; शोबिका इम्पेक्स (पी) लिमिटेड बनाम केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (2016) 16 एससीसी 233: [2016] 5 एससीआर 319; रौनक अंतराष्ट्रीय लिमिटेड बनाम आईवीआर निर्माण लिमिटेड (1999) 1 एससीसी 492: [1998] 3 सप्ल. एससीआर 421 - पर भरोसा.

आरडी शेटी बनाम भारतीय अन्तराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (1979) 3 एससीसी 489: [1979] 3 एससीआर 1014; टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651: [1994] 2 सप्ल. एससीआर 122; राम और श्याम

कंपनी बनाम हरियाणा राज्य (1985) 3 एससीसी 267: [1985] 1 सप्ल. एससीआर 541; मास्टर मरीन सेवा (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एवं हॉज किन्सन (पी) लिमिटेड (2005) 6 एससीसी 138: [2005] 3 एससीआर 666 - संदर्भित।

केस लॉ संदर्भ

[1979] 3 SCR 1014	को संदर्भित	अनुच्छेद 15
[1994] 2 सप्ल। SCR 122	को संदर्भित	अनुच्छेद 15
[1985] 1 सप्ल। SCR 541	को संदर्भित	अनुच्छेद 23
[2006] 10 सप्ल। SCR 606	पर निर्भर	अनुच्छेद 33
[1998] 3 सप्ल। SCR 421	पर निर्भर	अनुच्छेद 39
[2013] 12 SCR 529	पर निर्भर	अनुच्छेद 40
[2005] 3 एससीआर 666	पर निर्भर	अनुच्छेद 41
[2016] 5 एससीआर 319	पर निर्भर	अनुच्छेद 47

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 2197.

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.04.2018 से एलपीए संख्या 466/2017 में ।

के साथ।

2020 की सिविल अपील संख्या 2198, 2199 और 2200

के. के. वेणुगोपाल, ए.एन.एस.नाडकर्णी, एएसजी, पी. एस. नरसिम्हा, एन. के. कौल, डॉ. ए. एम. सिंघवी, अजीत कुमार सिन्हा, जमशेद पी. कामा, किरण सूरी, सीनियर एडवोकेट, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री अयियाला इम्ती, अंकुर तलवार, सुश्री चिन्मयी चंद्रा, मुनीश मल्होत्रा, मनप्रीत कौर, वान्या खन्ना, रजत भारद्वाज, आविष्कार सिंघवी, सुश्री ऐश्वर्या सिन्हा, आलोक के. सिंह, निपुण कात्याल, इवान, एल. निधराम शर्मा, अनिल कुमार मिश्रा-प्रथम, सुश्री सुरुचि कुमार, मय प्रसाद, इदरीश मोहम्मद, सुपंथ सिन्हा, रजनीश प्रसाद, मुकुल सिंह, सयूज मोहनदास, गुरमीत सिंह मक्कड़, अरविंद

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

कुमार शर्मा, संतोष शर्मा, बी.वी.बलराम दास
दिया गया था

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय

निर्णय

1. दी गई छुट्टी।
2. इन अपीलों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (इसके बाद, "बीसीसीएल") द्वारा रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठद्वारा पारित दिनांक 12.04.2018 के आदेश से व्यथित किया गया है, जिसमें एएमआर-देव प्रभा (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी गई थी और मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा आयोजित नीलामी प्रक्रिया इसके बाद "सी1-इंडिया") को अलग रखा गया था और बीसीसीएल द्वारा मैसर्स आरके ट्रांसपोर्ट कंपनी (प्रतिवादी नंबर 6) को निविदा के परिणामी अवार्ड को भी रद्द कर दिया गया था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बीसीसीएल, भारत में कोकिंग कोयला खानों का संचालन करती है और इसके संचालन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से बाहरी संस्थाओं को कई खनन और प्रसंस्करण कार्यों को आउटसोर्स करती है। कार्यों का ऐसा आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 4 [मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "सी1 इंडिया") - एक ऑनलाइन खरीद सुविधाकर्ता] को अपने अनुबंधों के ई-निविदा के लिए सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया जा रहा है।

4. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 09.03.2015 को निविदा आमंत्रित करने वाला एक नोटिस ("एनआईटी") जारी किया गया था, जिसके प्रयोजन से 'ओ बी को हटाने, निष्कर्षण और अग्निशमन के साथ कोयले के परिवहन के लिए XIV, XII, XI/XII, XII XI, IX/X, V/VI/VII/VIII, IV/VIII, IV(T), IV(B), III, II I(T) और I(B) सीमों से अग्निशमन के साथ कोयले की निकासी और परिवहन के साथ-साथ पोर्टबल द्वारा कोयले की पेराई के साथ-साथ क्रशर' (एनआईटी नंबर 312)। अपीलकर्ता द्वारा 1694.84 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुमान तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य उस फर्म को अनुबंधित

करना था जिसने निविदा कार्य को पूरा करने के लिए सबसे कम लागत अनुमान की पेशकश की थी।

5. बोली 04.05.2015 और 05.05.2015 को सी1-इंडिया के ऑनलाइन ई-रिवर्स नीलामी मंच पर आयोजित की जानी थी, जिसमें सी1-इंडिया के पास नीलामी प्रक्रिया पर पूर्ण पर्यवेक्षण और स्वायत्तता थी। बदले में, C1-इंडिया ने टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड ("TCL") के साथ अपने सर्वर की मेजबानी की थी, जो C1-इंडिया को लीड लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रदान कर रहा था। एनआईटी की शर्तों के अनुसार, नीलामी 05.05.2015 को शाम 6:00 बजे बंद हो जाएगी। हालांकि, अगर किसी विशेष बोली का 30 मिनट की अवधि तक जवाब नहीं दिया जाता है तो नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवा प्रदाता के अंत में किसी भी तकनीकी दोष के मामले में, नीलामी की अवधि को रोक दिया जाना था और गलती की अवधि तक बढ़ाया जाना था; हालांकि, बोलीदाताओं को अपनी ओर से कनेक्टिविटी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होना था।

6. यद्यपि नीलामी पहले दिन 05.05.2015 को लगभग 12:55 बजे सुचारु रूप से आगे बढ़ी, सी1-इंडिया को विभिन्न प्रतिभागियों से कुछ टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए जिनमें दावा किया गया कि कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं थीं जिसके कारण बोलियां प्रस्तुत करने में विफलता हुई। इस प्रकार सी1-इंडिया द्वारा टीसीएल को दोपहर 12:59 बजे एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया था कि "मेरा लिंक डाउन है"। जवाब में, टीसीएल ने दोपहर 2:11 बजे एक ईमेल के माध्यम से सी1-इंडिया को सूचित किया कि बैंडविड्थ मुद्दों को वास्तव में उनके इंटर-सिटी नेटवर्क में दोहरे फाइबर कट के साथ-साथ उनके पैच कॉर्ड में खराबी के कारण अनुभव किया गया था। इस बीच, मेसर्स एएमआर-देव प्रभा (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा दोपहर 12:33 बजे की गई 2345 करोड़ रुपये की अंतिम बोली तीस मिनट तक बिना जवाब दिए चली गई, और नीलामी स्वचालित रूप से दोपहर 1:03 बजे बंद हो गई।

7. टीसीएल द्वारा सूचित इन तकनीकी मुद्दों पर सचेत ध्यान देते हुए और यह अनुमान लगाते हुए कि कम कीमत का पता लगाया जा सकता है, अगर ऐसी गलती उत्पन्न नहीं हुई थी, सी1-इंडिया (कथित तौर पर बीसीसीएल

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

अधिकारियों की सहमति से) ने दोपहर 2:30 बजे नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। इस तरह के बहाली, समय के विस्तार की संभावना के साथ, सभी बोलीदाताओं को टेलीफोन पर सूचित किया गया था, साथ ही 2:17 बजे से 2:36 बजे के बीच भेजे गए ईमेल के माध्यम से भी। तदनुसार, कई प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न बोलियां प्राप्त की गईं, जिनमें अब पीड़ित प्रतिवादी नंबर 1 और अंततः सफल प्रतिवादी नंबर 6 से कई बोलियां शामिल हैं। नीलामी 1 घंटे 27 मिनट के विस्तारित समय तक आगे बढ़ी (दोपहर 1:03 बजे गलत बंद होने और बाद में 2:30 बजे फिर से शुरू होने के बीच रुकावट के समय के रूप में गणना की गई), और प्रतिवादी नंबर 6 को शाम 7:27 बजे 2043 करोड़ रुपये की बोली के साथ सफल घोषित किया गया।

8. यह बीसीसीएल को सूचित किया गया था, जिसने मेसर्स आरके ट्रांसपोर्ट (प्रतिवादी नंबर 6, इसके बाद "आरके ट्रांसपोर्ट") की पात्रता का आकलन करने के बाद, 30.05.2015 को स्वीकृति पत्र ("एलओए") जारी किया। पूर्व में सहमत संविदात्मक शर्तों के अनुसार, एलओए प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी थी। प्रतिवादी नंबर 6 ऐसा करने में असमर्थ था, और उसने बीसीसीएल से अनुपालन के लिए अतिरिक्त दो महीने प्रदान करने का अनुरोध किया। अपीलकर्ता ने 18.06.2015 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 सहित सभी असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा ("ईएमडी") वापस कर दी। अंत में, 49 दिनों की देरी के बाद अपेक्षित गारंटी प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलकर्ता द्वारा माफ कर दिया गया और जमीन पर काम शुरू किया गया।

9. नीलामी बंद होने के तीन महीने बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने 10.08.2015 को रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई कि यह 05.05.2015 को दोपहर 1:03 बजे सफल एल-1 बोलीदाता के रूप में उभरा, और अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 6 को जारी एलओए को मनमाना करने के लिए रद्द करने के लिए। इसके साथ ही, यह भी प्रार्थना की गई कि बीसीसीएल को उन्हें अनुबंध देने और पूरे मामले की जांच करने के निर्देश जारी किए जाएं।

10. रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 1 ने एनआईटी के खंड 20 को लागू किया, जिसमें एक अखंडता समझौते का प्रावधान किया गया था जिसके तहत दो स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर ("आईईएम") नियुक्त किए गए थे। 23.09.2016 को इन दो आईईएम में से एक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई तकनीकी समस्या नहीं थी और दोपहर 2:30 बजे नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना अनुचित था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह रिपोर्ट पहले आईईएम द्वारा एकतरफा कार्य करते हुए और सी1-इंडिया और आरके ट्रांसपोर्ट को सुने बिना प्रस्तुत की गई थी।

11. इसके साथ ही, अपीलकर्ता ने दूसरे आईईएम से संपर्क किया, जिसने सभी पक्षों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद एक अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह अवलोकन किया गया कि मिलीभगत की कोई संभावना नहीं थी और यह देखते हुए कि बैंडविड्थ में रुकावट स्थापित की गई थी और इस प्रकार सी1-इंडिया द्वारा बाद में फिर से शुरू किया गया था।

12. इस तरह के संघर्ष के प्रकाश में, बीसीसीएल ने पहले मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) निदेशालय से संपर्क किया और अंकेक्षण की मांग की, और बाद में विवाद की तकनीकी प्रकृति के कारण ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की; अपीलकर्ता ने CERT-In (भारत सरकार के संचार और IT मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र निकाय) के महानिदेशक से संपर्क किया। इसके बाद सीईआरटी-इन द्वारा 30.12.2015 को बीसीसीएल को एक 'घटना विश्लेषण रिपोर्ट' प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर दूसरे आईईएम की टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की गई और पाया गया कि यह प्रक्रिया मिलीभगत से प्रभावित नहीं थी, और कनेक्टिविटी समस्याओं के अस्तित्व की पुष्टि की जिसके कारण नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना आवश्यक हो गया।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

13.16.08.2017 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले प्रतिवादी की रिट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बीसीसीएल द्वारा सभी को एक समान खेल मैदान प्रदान किया गया थावास्तव में एक कनेक्टिविटी मुद्दा था और नीलामी की बाद में फिर से शुरुआत एनआईटी की शर्तों के अनुसार थी; आरके ट्रांसपोर्ट को ठेका देना मनमाना नहीं था क्योंकि उसने न केवल एल-1 की बोली लगाई थी बल्कि एएमआर-देव प्रभा की तुलना में काफी बेहतर बोली की पेशकश भी की थी। इसके अलावा, पहले प्रतिवादी को फिर से शुरू की गई नीलामी में भाग लेकर प्रक्रिया में किसी भी संभावित अनियमितता को स्वीकार करने के लिए माना गया था, और आरके ट्रांसपोर्ट द्वारा गारंटी प्रस्तुत करने में देरी की बीसीसीएल की माफी को स्वीकार्य और सार्वजनिक हित में माना गया था।

14. इसे प्रतिवादी नंबर 1 ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। लेटर्स पेटेंट अपील के लंबित रहने के दौरान, 18.09.2017 को, एएमआर-देव प्रभा के वकील ने नौकरी के लिए 1950 करोड़ रुपये की कम बोली की पेशकश की, जिसे उन्होंने 2345 करोड़ रुपये की अपनी पिछली बोली से कहीं बेहतर बताया, जो उन्होंने 05.05.2015 को दोपहर 12:33 बजे की थी। हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था और इसके बजाय 23.11.2017 को प्रतिवादी नंबर 6 को एक कार्य आदेश जारी किया गया था, जिसने शीघ्र ही काम शुरू कर दिया था।

15. खंड पीठने दिनांक 12.04.2018 के आक्षेपित निर्णय के तहत अपील की अनुमति दी और आर.के परिवहन के पक्ष में बीसीसीएल द्वारा जारी एल ओ ए को रद्द कर दिया और माना कि सभी परिणामी कार्य अमान्य थे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आगे नीलामी को फिर से आयोजित करने का निर्देश दिया और मामले में सतर्कता जांच का आदेश दिया। **आरडी शेटी बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आइ)¹** और **टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ²** के अनुपात का संज्ञान जहां इस न्यायालय ने निविदा मामलों में न्यायिक समीक्षा की व्यापकता और अनुमति को स्पष्ट किया था, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह परिणाम से संबंधित नहीं था, बल्कि केवल कार्य-अनुबंध देने का निर्णय लेने के तरीके से संबंधित था।

¹(1979)3 एस सी सी 489

²(1994)6 एस सी सी 651

16. एनआईटी की शर्तों का विश्लेषण करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि प्रणाली आवश्यकताओं का पालन करना बोलीदाता की जिम्मेदारी थी, बीसीसीएल किसी भी तकनीकी कठिनाइयों या कनेक्टिविटी विफलताओं के लिए उत्तरदायी नहीं था। निविदा को केवल सेवा प्रदाता की ओर से प्रौद्योगिकीय/प्रणाली में खराबी आने पर ही रोका जा सकता है और एक बार पूरा हो जाने पर सीमित परिस्थितियों में ही वापस लिया जा सकता है। न केवल सी1-इंडिया के लिए गैर-कार्रवाई योग्य शिकायतें लगातार टीसीएल से जुड़ी हुई थीं, जिसका अर्थ था कि सेवा प्रदाता की ओर से कोई समस्या नहीं थी, बल्कि अन्यथा भी सी1-इंडिया महत्वपूर्ण अवधि के दौरान नीलामी प्रक्रिया को रोकने में विफल रहा, जो इसे एनआईटी की शर्तों के अनुसार होना चाहिए था।

17. बोलीदाताओं द्वारा किसी भी कॉल रिकॉर्ड या तकनीकी शिकायतों के अन्य प्रमाण की अनुपस्थिति, नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के संचार में देरी (यह देखते हुए कि कैसे 2:37 बजे तक ईमेल भेजे गए थे जबकि नीलामी 2:30 बजे फिर से शुरू हुई थी), एएमआर-देव प्रभा की एल 1 बोलीदाता के रूप में घोषणा को रद्द / निरस्त करने में विफलता और विस्तारित समय की गलत गणना (7:35 बजे के बजाय 7:27 बजे), न्यायालय ने कहा कि बीसीसीएल और सी1-इंडिया नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने में विफल रहे और गंभीर अवैधता की जिससे प्रक्रियात्मक औचित्य पर संदेह पैदा हुआ और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानेपन का संकेत मिला। एनआईटी की शर्तों से इस तरह के विचलन को न केवल विपथन माना गया था, बल्कि निष्पक्ष खेल की पूर्ण कमी का संकेत दिया गया था जिसने पूरी प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया, इसे सार्वजनिक हित के विपरीत और परिणामस्वरूप अवैध बना दिया।

पक्षकारों की दलीलें

18. मुख्य रूप से प्रारंभिक मामलों में उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए, बीसीसीएल ने जोरदार तर्क दिया कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जहां न्यायिक समीक्षा संभव थी। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य या उसके साधनों के संविदात्मक व्यवहार में रिट क्षेत्राधिकार का दायरा बेहद सीमित था, और वाणिज्यिक ज्ञान का सम्मान था। कार्यकारी आदर्श होना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अवैध

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

नहीं दिखाया गया था क्योंकि बाहरी परितोषण प्राप्त करने या किसी कानून के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं था; न ही तर्कहीन क्योंकि बेहतर कीमत पर पहुंचने के लिए नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय ऐसा नहीं था जो एक उचित व्यक्ति की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाएगा; न ही मनमाना क्योंकि एनआईटी की शर्तों द्वारा पर्याप्त विवेक दिया गया था। फिर से शुरू होने के बाद निविदा प्रक्रिया में प्रतिवादी नंबर 1 की भागीदारी को उसे आगे कोई न्यायिक चुनौती देने से रोकने के लिए तर्क दिया गया था, और अनुबंध और नागरिक कानून के तहत वैकल्पिक उपायों का प्रदर्शन किया गया था। आगे यह कहा गया कि पूरी प्रक्रिया को कई स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा बरकरार रखा गया था, कम से कम सीईआरटी-इन और दो आईईएम में से एक नहीं था।

19. इस तरह के रुख को अपनाते हुए, प्रतिवादी नंबर 4 (सी1-इंडिया) ने तर्क दिया कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में थोड़ी देरी, जिसमें उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एक जिम्मेदार ई-सेवा प्रदाता के रूप में सी1-इंडिया पहले यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहा था कि रुकावट बोलीदाताओं के अंत में थी या स्वयं की थी। जब तक मेजबानी और संयोजकता (यानी टीसीएल) के लिए जिम्मेदार इकाई से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, तब तक नीलामी अपने आप बंद हो गई थी। इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि दोपहर 2:11 बजे टीसीएल से लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर, सी1-इंडिया ने बीसीसीएल के परामर्श से तेजी से निर्णय लिया, और सभी प्रतिभागियों को सूचित करना शुरू कर दिया और दोपहर 2:30 बजे बोली फिर से शुरू की। यह रेखांकित किया गया कि किसी भी बोलीदाता के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 के पास बोली लगाने का पर्याप्त अवसर था, क्योंकि इसने फिर से शुरू की गई समय सीमा के दौरान आठ बोलियां प्रस्तुत कीं। इसके अलावा, इस तरह की भागीदारी के साथ तीन महीने तक चुप्पी के बाद यह स्पष्ट है कि एएमआर-देव प्रभा खुद को एल-1 नहीं मानती थीं और वर्तमान कानूनी चुनौती वाणिज्यिक अवसरवाद के अलावा और कुछ नहीं थी। विस्तारित समय की गणना के संबंध में, सी1-इंडिया के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह महत्वहीन था क्योंकि विस्तार की मात्रा सभी बोलीदाताओं को समान रूप से सूचित की गई थी, और सभी के पास समान जानकारी थी और इसलिए एक समान अवसर था। बहाली का निर्णय अच्छे विश्वास में और सभी कारकों पर विवेकपूर्ण विचार करने पर

लिया गया था। इसे जनहित में माना गया और पीछे मुड़कर देखने पर इससे सरकारी खजाने को पर्याप्त बचत ही हुई।

10. अपीलकर्ता के वकील के साथ-साथ C1-इंडिया के लिए इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे पूरे मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा गोलपोस्ट को बदला जा रहा था। जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष एएमआर-देव के प्रभा ने एनआईटी की शर्तों का पालन करने और सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन की मांग की, लेकिन बाद में उन्होंने बड़े जनहित का दावा करते हुए मामले को कम कीमत पर निपटाने की इच्छा जताई। यह प्रदर्शित करने के लिए दावा किया गया था कि एएमआर-देव प्रभा की रुचि वास्तव में व्यक्तिगत थी और सार्वजनिक नहीं थी, और केवल एक या दूसरे तरीके से निविदा जीतने के लिए और नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नहीं। ऑन-द-स्पॉट विरोध की कमी, न तो नीलामी प्रक्रिया के दौरान, और न ही बयाना धन जमा की वापसी का लाभ उठाने के समय; और रिट याचिका दायर करने में पर्याप्त देरी (नीलामी प्रक्रिया के बंद होने के 3 महीने से अधिक और एलओए जारी होने से 2 महीने के बाद) मुकदमेबाजी से बाहर एक व्यावसायिक अवसर बनाने के उद्देश्य से एक बाद के विचार के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए, वर्तमान कार्यवाही को एएमआर-देव प्रभा द्वारा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होने का दावा किया गया था और केवल बीसीसीएल को निविदा देने के लिए हाथ घुमाने का मौका था, निजी अधिकारों के संविदात्मक प्रवर्तन से बेहतर नहीं था।

21. इसके बजाय, यह प्रस्तुत किया गया था, कि कोई भी संभावित दुर्बलता केवल मामूली और महत्वहीन थी। निविदा प्रक्रिया और निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के खंडों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था, और न्यूनतम मूल्य खोज सुनिश्चित करने के सार्वजनिक हित को सबसे आगे रखा गया था। यह तर्क दिया गया था कि हाइपर तकनीकी अनुपालन अक्सर संभव नहीं था, न ही वांछनीय था क्योंकि अक्सर सख्त प्रक्रियात्मक अनुपालन वर्तमान मामले की तरह वास्तविक समानता के सिरो को हरा सकता है।

22. इस प्रक्रिया में किसी भी दुर्भावना या छेड़छाड़ की कमी को प्रदर्शित करने के लिए सीईआरटी-आईएन रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था। टीसीएल के अंत में रुकावटों को

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

स्वाभाविक और परिचालन अक्षमताओं का एक हिस्सा होने का दावा किया गया था जो ई-निविदा प्रक्रियाओं में अनसुना नहीं था।

23. दूसरी तरफ, प्रतिवादी नंबर 1 ने दावा किया कि इसे 1:03 बजे नीलामी प्रक्रिया के स्वचालित समापन के आधार पर सबसे कम बोली लगाने वाले (एल -1) के रूप में घोषित किया गया था, जिसके बाद कोई भी बहाली अस्वीकार्य थी और संविदात्मक शर्तों के विपरीत थी। इसके अलावा, यह दावा करते हुए एक रंग डालने की कोशिश की गई थी कि इस तरह की बहाली विशेष पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए थी। बीसीसीएल द्वारा नई बोली को स्वीकार करने से इनकार करना, जो पिछले प्रस्ताव की तुलना में 400 करोड़ रुपये से अधिक कम था, इसे प्रदर्शित करने का दावा किया गया था। एएमआर-देव प्रभा के अनुसार, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो **राम और श्याम कंपनी बनाम हरियाणा राज्य**³ के अनुसार है। हरियाणा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य साधन औपचारिक तकनीकी के बावजूद सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य को स्वीकार करे।

24. फिर से शुरू बोली प्रक्रिया में प्रतिवादी 1 की भागीदारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि फिर से शुरू करना ही अवैध था। नीलामी बंद कर दी गई थी और रुकी नहीं थी, और इसलिए बंद बोली प्रक्रिया को फिर से शुरू करना संभव नहीं था। अन्यथा भी, यह दावा किया गया था कि 1 घंटे और 27 मिनट का विस्तार देना गलत था। समय की गणना उस समय से की जानी चाहिए जब अंतरजाल प्रभावित हुआ था, जो अपीलकर्ता के अनुसार स्वयं दोपहर 12:55 बजे से था, जैसा कि टीसीएल द्वारा उन्हें सूचित किया गया था। इसलिए 1 घंटा 35 मिनट (और 1 घंटा 27 मिनट नहीं) का विस्तार उचित था, जिसके अनुसार नीलामी शाम 7:35 बजे समाप्त होनी चाहिए थी, न कि 7:27 बजे। इसी तरह, दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू करने के लिए ईमेल, कुछ प्रतिभागियों को दोपहर 2:17 बजे और दूसरों को 2:36 बजे भेजे गए थे। इसके अलावा, दो व्यक्तियों को ई-नीलामी प्रक्रिया फिर से शुरू होने से एक मिनट पहले दोपहर 2:29 बजे सिस्टम में लॉग इन करने का दावा किया गया था, जिसने उन्हें ई-नीलामी प्रक्रिया में गलत तरीके से ऊपरी हाथ दिया था। एक इकाई द्वारा दो खातों का उपयोग करके लॉगिन करने के बारे में अन्य आरोप भी लगाए गए थे,

3. (1995) 3 एस सी सी 267

जिन्हें एनआईटी के अनुसार अस्वीकार्य माना गया था। 25. यह सब पूरी नीलामी प्रक्रिया पर संदेह के गंभीर बादल डालने के लिए पोस्ट किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान भी, सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए दिनांक 04.11.2015 के आदेश का पालन करने के बजाय, बीसीसीएल ने मामले को सीईआरटी-इन को संदर्भित करने के लिए कहा था। हालांकि, पहले आईईएम ने माना था कि अपीलकर्ता का सर्वर (1985) 3 एससीसी 267

टीसीएल के सर्वर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था और अपीलकर्ता की ओर से कोई 3 समस्या नहीं थी जिसके लिए नीलामी प्रक्रिया को रोकने या फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी।

26. रखरखाव पर, हालांकि प्रतिवादी नंबर 1 ने वैकल्पिक उपचार होने की बात स्वीकार की, लेकिन यह तर्क दिया कि रिट अदालतों के पास जाने से रोकने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। देरी के बिंदु पर, उनके जवाबी हलफनामे में, प्रतिवादी नंबर 1 ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी नंबर 6 निविदा खंड के अनुसार 28 दिनों के भीतर प्रदर्शन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहने के बाद कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।

27. रिट याचिका की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपीलकर्ता को किए गए प्रस्ताव पर पर्याप्त जोर दिया गया था, जिसकी अस्वीकृति को सार्वजनिक हित और स्थापित कानून के विपरीत होने का दावा किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक खजाने के मूल्य को अधिकतम करने को प्राथमिकता देना है।

विश्लेषण

28. उपरोक्त चर्चा से दो स्पष्ट मुद्दे उठते हैं। पहला निविदा प्रक्रियाओं की प्रकृति पर विचार करते हुए रिट की स्थिरता से संबंधित है, और दूसरा वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उस मानक के आवेदन से संबंधित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बीसीसीएल और सी1-इंडिया की ओर से चूक हुई थी या नहीं।

(i) रिट याचिका की अनुरक्षणीयता

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

29. निविदाओं में न्यायिक समीक्षा के दायरे का गहराई से पता लगाया गया है। यह तय है कि संवैधानिक अदालतें केवल किसी निर्णय की वैधता से संबंधित हैं, न कि इसकी ध्वनि से.⁴ अलग तरीके से कहें तो, न्यायालयों को कार्यकारी अधिकारियों या साधनों के निर्णयों पर अपील में नहीं बैठना चाहिए। प्रशंसनीय निर्णयों को पलटने की आवश्यकता नहीं है⁵, और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में राज्य को अक्षांश दिया जाना चाहिए ताकि शक्तियों के संवैधानिक पृथक्करण का अतिक्रमण न हो। यह हमारी अनूठी घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से सच है, जिसने कई बार न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता का प्रदर्शन किया है। इसलिए, यह केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया होगी जो न्यायिक जांच का विषय होगी, न कि अंतिम परिणाम (पूर्व के निर्धारण को निर्देशित करने के लिए आवश्यक को छोड़कर)।

30. कानून की इस स्थिति को संक्षेप में **टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ(सुप्रा)**, में अभिव्यक्त किया गया है। जहां यह प्रसिद्ध रूप से कहा गया था कि:

"77. ... इसलिए, यह निर्धारित करना न्यायालय का काम नहीं है कि उस नीति को पूरा करने में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी। संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (i) *अवैधता: इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और इसे प्रभावी करना चाहिए।*

⁴ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम संघ), (2016) 8 एससीसी 622; सीमेंस एक्टिंगेसेलिशाफ्ट और सीमेंस लिमिटेड बनाम डीएमआरसी लिमिटेड, (2014) 11 एससीसी 288.

⁵ एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2000) 2 एससीसी 617.

4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एसएलएल-एसएमएल (संयुक्त उद्यम कंसोर्टियम), (2016) 8 एससीसी 622; सीमेंस एक्टिंगेसेलिशाफ्ट एंड सीमेंस लिमिटेड बनाम डीएमआरसी लिमिटेड, (2014) 11 एससीसी 288. 5 एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (2000) 2 एससीसी 617

(ii) तर्कहीनता, अर्थात्, वेडनेसबरी तर्कहीनता,

(iii) प्रक्रियात्मक अनौचित्यता।“

31. लेकिन केवल इसलिए कि लगाए गए आरोप राज्य या उसके तंत्रों के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एक पीड़ित व्यक्ति स्थापित नागरिक न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकता है और सीधे रिट राहत प्राप्त कर सकता है। यह निर्धारित करने में कि क्या अपने विवेक का प्रयोग करना है, रिट अदालतों को न केवल खुद को विपरीत पक्ष की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, बल्कि विवाद की प्रकृति और राहत के लिए प्रार्थना की गई है। इस प्रकार, हालांकि हर गलत का एक उपाय होता है, गलत की प्रकृति के आधार पर निवारण के लिए अलग-अलग मंच होंगे।

32. ऐसे मामलों में जहां एक संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है, रिट आमतौर पर उचित उपाय होगा। निविदा मामलों में, ऐसा तब हो सकता है जब कोई पार्टी राज्य को सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने के अपने कर्तव्य के लिए पकड़ना चाहती है या इसे मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है; या जब कार्यकारी कार्यों या विधायी उपकरणों को व्यापार और वाणिज्य पर ले जाने की स्वतंत्रता के उल्लंघन में होने के लिए चुनौती दी जाती है। हालांकि, रिट अस्वीकार्य हैं जब आरोप पूरी तरह से एक संविदात्मक अधिकार या कर्तव्य के उल्लंघन के संबंध में है। इसलिए, रिट राहत मांगने वाले व्यक्तियों को भी न्यायालय को सक्रिय रूप से संतुष्ट करना चाहिए कि वह जो अधिकार मांग रहा है वह सार्वजनिक कानून में एक है, न कि केवल संविदात्मक है। ऐसा करने में, वाणिज्यिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और मिलीभगत, अवैधता और सार्वजनिक संसाधनों की फिजूलखर्ची की वास्तविक संभावना के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

33. इस तरह के प्रस्ताव को इस न्यायालय ने पहले भी **जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य**⁶ मामले में देखा है। 6(2007)14 एस सी सी 517

“22 में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, तर्कहीनता, पक्षपात और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या चुनाव या निर्णय "कानूनी" रूप से किया गया है और यह जांचना नहीं है कि चुनाव या निर्णय "ध्वनि" है या नहीं। जब निविदाओं या अनुबंधों के आवंटन से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत दूरी पर रहते हैं। यदि संविदा प्रदान करने से संबंधित निर्णय सदाशयी है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगी, यदि किसी निविदाकर्ता के प्रति कोई प्रक्रियात्मक विपथन या मूल्यांकन में त्रुटि या पूर्वाग्रह किया जाता है तो भी हस्तक्षेप किया जाता है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हितों की रक्षा के लिए, या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए लागू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत के साथ निविदाकर्ता या ठेकेदार हमेशा सिविल कोर्ट में नुकसान की मांग कर सकता है। काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकर्ताओं द्वारा कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के तिल से पहाड़ बनाने और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करने के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, चाहे अंतरिम हों या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और परियोजना लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

⁶ (2007) 14 एससीसी 517

(महत्व दिया गया)

34. इस तरह के सचेत संयम भी आवश्यक है क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप से समय और धन का प्रभाव पड़ता है, जो अगर अनियंत्रित होता है तो निजी संस्थाओं के साथ अनुबंध और व्यापार में प्रवेश करने की राज्य की क्षमता पर समस्याग्रस्त प्रभाव पड़ता। इसके अलावा, अदालतों के लिए हर दिन कार्यकारी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए हजारों अनुबंधों की समीक्षा करना वांछनीय या व्यावहारिक नहीं है। न्यायालयों को यह भी पता होना चाहिए कि अक्सर कुछ लोगों के निजी हित जनता के सार्वजनिक हित से टकरा सकते हैं, और इसलिए इस न्यायालय द्वारा 'सार्वजनिक हित' पर प्रभाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता विकसित की गई है।⁷

35. इस प्रकार यह जरूरी है कि अनुच्छेद 14 के तहत मनमानेपन, अवैधता या भेदभाव या अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत स्वतंत्रता के अतिक्रमण के अलावा, उपाय मांगने से पहले सार्वजनिक हित का भी प्रदर्शन किया जाए। यद्यपि उत्तरार्द्ध के लिए सीमा उच्च होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सिविल अदालतों को दरकिनार करने और संविदात्मक दायित्वों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक रास्ते के उपयोग को रोकना आवश्यक है।

36. वर्तमान मामले में, हालांकि यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठन्यायिक समीक्षा के दायरे के आसपास के इन सिद्धांतों से अवगत थी, हालांकि, यह प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने में विफल रही कि क्या व्यापक जनहित प्रभावित हो रहा था। इसके विपरीत, हमें लगता है कि प्रतिवादी नंबर 1 का हित विशुद्ध रूप से निजी और मौद्रिक प्रकृति का था।

37. सबसे पहले, एएमआर-देव प्रभा की प्रारंभिक प्रार्थना ने अनुबंध के पुरस्कार को रद्द करने की मांग की, जो अगर दी जाती, तो राज्य द्वारा देय राशि 2043 करोड़ रुपये से बढ़कर 2345 करोड़ रुपये हो जाती। दूसरा, वर्तमान कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 का आचरण, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा उजागर किया गया है, सार्वजनिक हित की कमी को और बढ़ाता है। जबकि शुरू में पहला प्रतिवादी बीसीसीएल की ओर से

⁷ जगदीश मण्डल बनाम उड़ीसा , (2007) 14 एससीसी 517/22

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

मनमानी के कारण प्रतिवादी नंबर 6 को जारी एलओए को रद्द करने की मांग कर रहा था और इस आधार पर कि नीलामी प्रक्रिया की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था; बाद में, खंड पीठके समक्ष, प्रतिवादी नंबर 1 ने 1950 करोड़ रुपये की नई पेशकश करने की मांग की। इससे पता चलता है कि एएमआर-देव प्रभा की प्राथमिकता केवल अनुबंध को सुरक्षित करना था न कि कानून को बनाए रखना या बड़े जनहित की रक्षा करना।

38. अन्यथा भी, इस तरह की प्रार्थना देने का मतलब है कि प्रतिवादी नंबर 1 को बातचीत का एक विशेष अवसर मिला होगा, अन्य सभी प्रतिभागियों की हानि के लिए, जो शायद अनुच्छेद 14 के तहत परिकल्पित समानता का अधिक गंभीर उल्लंघन होगा प्रक्रियात्मक पालन की तुलना में जो वे शुरू में रक्षा करने की मांग कर रहे थे।

39. इसके अतिरिक्त, हम पहले प्रतिवादी के तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि जब भी सार्वजनिक राजकोष शामिल होता है तो दांव पर एक निश्चित सार्वजनिक हित होता है। केवल बोली लगाने की कीमत के अलावा विभिन्न कारक हैं, जैसे तकनीकी क्षमता और समय पर पूरा होना जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस तरह की व्याख्या को अपनाने से राज्य से जुड़े संविदात्मक विवादों और सार्वजनिक कानून को प्रभावित करने वालों के बीच की रेखा स्थायी रूप से धुंधली हो जाएगी। इसे **रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम आईवीआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड⁸** में उपयुक्त रूप से उजागर किया गया है

"11. जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य द्वारा अनुबंध के पुरस्कार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाती है, तो अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी याचिका पर विचार करने में सार्वजनिक हित का कुछ तत्व शामिल है। यदि, उदाहरण के लिए, विवाद विशुद्ध रूप से दो निविदाकर्ताओं के बीच है, तो अदालत को यह देखने के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि क्या मुकदमेबाजी में सार्वजनिक हित का कोई तत्व शामिल है। दो निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमतों में मात्र अंतर यह तय करने में निर्णायक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में हस्तक्षेप करने में कोई सार्वजनिक हित शामिल है या नहीं। यह ध्यान में रखना

⁸ (1999) 1 एस सी सी 492, 9 (2014) 3 एस सी सी 760

महत्वपूर्ण है कि अदालत के हस्तक्षेप से, प्रस्तावित परियोजना में काफी देरी हो सकती है जिससे लागत कहीं अधिक बढ़ जाती किसी भी बचत की तुलना में जो अदालत अंततः एक निविदाकर्ता या दूसरे निविदाकर्ता के पक्ष में विवाद का फैसला करके सार्वजनिक धन में प्रभाव डालेगी। इसलिए, जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती है कि सार्वजनिक हित की पर्याप्त मात्रा है, या लेनदेन दुर्भावनापूर्ण रूप से दर्ज किया गया है, अदालत को दो प्रतिद्वंद्वी निविदाकर्ताओं के बीच 8(1999)1 एस सी सी 492

विवादों में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(महत्त्व सन्निविष्ट)

40. इसके अलावा, पहला प्रतिवादी यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि वह किस सार्वजनिक कानून का दावा कर रहा था। एएमआर-देव प्रभा के मामले का मुख्य जोर इस तथ्य पर रहा है कि 05.05.2015 को दोपहर 1:03 बजे इसे सबसे कम बोलीदाता (या एल-1) घोषित किया गया था। हालांकि, एल-1 बोलीदाता घोषित होने से किसी भी इकाई को अनुबंध देने के लिए एक सार्वजनिक कानून पात्रता प्रदान नहीं की जाती है, जैसा कि **मा बिंदा एक्सप्रेस कैरियर बनाम नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर रेलवे**⁹ में उल्लेख किया गया है:

"8. राज्य और उसके तंत्रों द्वारा संविदा प्रदान करने से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा इस न्यायालय के निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा तय किया गया है। हालांकि इन निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि संविदा के आबंटन के संबंध में सरकार और उसके तंत्रों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति किसी पीड़ित पक्ष के कहने पर न्यायिक समीक्षा के अध्यक्षीन है, तथापि ऐसी निविदाएं आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रत्युत्तर में निविदा प्रस्तुत करना एक प्रस्ताव बनाने से अधिक नहीं है जिसे स्वीकार करने के लिए राज्य अथवा उसकी एजेंसियां बाध्य नहीं हैं। **अतः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि उनकी निविदाओं को केवल इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि**

⁹ (2014) 3 एससीसी 760

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

दी गई निविदा उच्चतम या निम्नतम है जो इस बात पर निर्भर करती है कि ठेका सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री के लिए है या सरकार की ओर से कार्यों के निष्पादन के लिए है। प्रतिभागी बोलीदाता अपनी निविदाओं के मूल्यांकन के मामले में केवल उचित, समान और गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार के हकदार हैं।

यह भी काफी अच्छी तरह से तय है कि एक अनुबंध का आवंटन अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक लेनदेन है जिसे इस तरह के वाणिज्यिक निर्णय के लिए प्रासंगिक विचार के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिन शर्तों के अधीन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, वे न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि इसे किसी विशेष निविदाकर्ता 9 (2014) 3 एससीसी 760 के लाभ के लिए तैयार किया गया है। या निविदाकारों का वर्ग। इसी तरह, निविदाएं आमंत्रित करने वाला प्राधिकरण बातचीत में प्रवेश कर सकता है या वास्तविक और ठोस कारणों के लिए छूट प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि निविदा प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली शर्तों के तहत इस तरह की छूट की अनुमति हो।“

(महत्व सन्निविष्ट)

41. इसके बजाय, *मास्टर मरीन सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम मेटकाफ एंड हॉज किंसन (पी) लिमिटेड*¹⁰, में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल से पता चलता है कि अगर फिर से बोली लगाने के लिए प्रार्थना एक बेहतर कीमत पाने की इच्छा के कारण है, तो संविधान के अनुच्छेद 14 की भागीदारी नहीं बनाई जाएगी.

42. इसके अलावा, एनआईटी की शर्तों पर पहले प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कार्यवाही के दौरान नियमित सहारा लिया गया था। आक्षेपित आदेश में निष्कर्ष भी इस तरह के संविदात्मक शर्तों की विवादित व्याख्या पर आधारित थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न तो पहले प्रतिवादी का कोई सार्वजनिक कानून अधिकार था जो प्रभावित हुआ था, न ही किसी सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी।

(II) नीलामी प्रक्रिया में कमजोरियां

¹⁰ 10 (2005) 6 एस सी सी 138, 11 (2016) 16 एस सी सी 233

43. गुण-दोष के आधार पर भी, हमें नहीं लगता कि आक्षेपित आदेश अपने निष्कर्ष में सही है कि बीसीसीएल और सी1-इंडिया की ओर से पर्याप्त प्रक्रियात्मक खामियां थीं जो मनमानी हैं, और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसे दूर किया जाना चाहिए।

44. इसके बजाय, केंद्रीय सतर्कता आयोग ("सीवीसी") की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट का लाभ होने के कारण, हम दृढ़ राय के हैं कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 दोनों ने अपनी क्षमताओं के अनुसार एक सदाशयी तरीके से काम किया। भले ही यह सच है कि बीसीसीएल अधिक जिम्मेदारी ग्रहण कर सकता था और सी1-इंडिया इंटरनेट मुद्दों की जांच में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता था, फिर भी सुधार की संभावना प्राधिकरण की कार्रवाई को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अवैध परितोषण द्वारा उच्चारण किए जा रहे निर्णयों का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, या अन्यथा धोखाधड़ी या कानून के विपरीत या तो स्पष्ट रूप से बनाया गया है या स्थापित नहीं किया गया है।

45. इस प्रकार सीवीसी द्वारा आयोजित तथ्यान्वेषी जांच के समापन मार्ग को पुनः पेश करना इस स्तर पर उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार पढ़ता है: पीठ ने कहा,

“यह रिकॉर्ड में लाना महत्वपूर्ण है कि 05 मई 2015 को 05 मई को 13:03:47 बजे प्रणाली द्वारा उत्पन्न रिवर्स नीलामी को बंद करने की अधिसूचना वास्तव में एक अन्य बोलीदाता मेसर्स मॉटेकार्लो लिमिटेड की है। न तो बीसीसीएल और न ही सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कभी भी इस तरह की अधिसूचना को रिकॉर्ड पर रखा है। यह स्पष्ट नहीं है कि मेसर्स एएमआर देव प्रभा को यह दस्तावेज कैसे और कब मिला, जो वास्तव में मेसर्स मॉटेकार्लो लिमिटेड का था और जो मेसर्स एएमआर देव प्रभा के लिए 13.03.47 बजे सबसे कम बोली लगाने का दावा करने का आधार बन गया। यह भी देखा गया है कि प्रणाली द्वारा 130347 बजे नीलामी बंद करने की अधिसूचना सृजित होने के इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में मेसर्स एएमआर देव प्रभा की बोली 30 मिनट की विनिदष्ट अवधि तक उत्तर नहीं दी गई, इसकी सूचना न तो सी 1 इंडिया द्वारा बीसीसीएल को दी गई थी और न ही प्रतिभागी बोलीदाताओं को। नीलामी की समाप्ति की ऐसी अधिसूचना, यद्यपि सर्वर के साथ बोलीदाताओं की कनेक्टिविटी में व्यवधान की अवधि के दौरान उत्पन्न हुई थी, नीलामी प्रक्रिया को

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

पुन शुरु करने से पहले शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए था। यहां तक कि, बीसीसीएल ने रुकावट अवधि के लिए सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से किसी भी रिपोर्ट की मांग नहीं की ताकि रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए आगे बढ़ने से पहले एक निर्णय लिया जा सके। इसके अलावा, इस बात पर विचार करते हुए कि इस अवधि के दौरान बीसीसीएल को बोलीदाताओं द्वारा सामना की जा रही कनेक्टिविटी समस्या की जानकारी थी, इसे गहन वास्तविक समय निगरानी करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। ऐसा करने में विफलता इस तथ्य का प्रतिबिंब है कि सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस तरह की घटना को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त घटना प्रबंधन प्रणाली नहीं लगाई गई थी। हालांकि बीसीसीएल की ओर से नियंत्रण और पर्यवेक्षण की कमी थी, तथापि, समिति को ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चले कि उनकी ओर से दुर्भावना है। जहां तक सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सवाल है, उनका आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।

46. हम सीमित बैंडविड्थ की तकनीकी समस्याओं के अस्तित्व में उद्यम करने के लिए आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि यह तथ्य का प्रश्न है। तथापि, दूसरे आईईएम, सर्टिन, टीसीएल और सीवीसी के समवर्ती निष्कर्षों को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि खण्ड न्यायपीठ ने यह कहते हुए गलती की कि कोई तकनीकी कठिनाइयां नहीं थीं। इसके अलावा, ऐसा निष्कर्ष बाद की घटनाओं के साथ है। इंटरनेट की कोई समस्या नहीं थी, इसका मतलब है कि किसी अन्य बोलीदाता ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दोपहर 12:33 बजे पेश की गई 2345 करोड़ रुपये की बोली का मुकाबला करना उचित नहीं समझा और यह प्रतिस्पर्धी रूप से निर्धारित सबसे कम कीमत थी। हालांकि, यह स्पष्ट है कि नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के मिनटों में बोलियां आने लगीं और बाद में एक दर्जन से अधिक बोलियां प्राप्त हुईं, जिसमें 2043 करोड़ रुपये की अंतिम बोली शाम 7:27 बजे नीलामी बंद होने से कुछ सेकंड पहले ही लगाई गई थी।

47. प्रतिवादी नंबर 6 की गारंटी देने में देरी के लिए माफी से संबंधित अन्य आरोपों के संबंध में, हम केवल यह दोहराएंगे कि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ

कानून में कोई निषेध नहीं है जो वास्तविक कारणों से छूट देते हैं। शोबिका इम्पेक्स (पी) लिमिटेड बनाम सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी¹¹ में, यह नोट किया गया है कि:

“यह है क्योंकि नोटिस एक कार्यकारी निर्णय पलटने के प्रभाव और लागत *overruns* या देरी के रूप में बड़े सार्वजनिक हित पर इसके प्रभाव के रखा जाना चाहिए. 49. समय विस्तार की मात्रा से संबंधित प्रश्नों में उद्यम करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि सीआई-इंडिया द्वारा सभी को एक ही संदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्रक्रिया को दोपहर 1:03 बजे नीलामी बंद होने और दोपहर 2:30 ब... राज्य किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनी पद्धति चुन सकता है और यदि निविदा की शर्तें ऐसी छूट की अनुमति देती हैं तो वह वास्तविक कारणों से कोई भी छूट प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है। आगे यह माना गया है कि राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधितों के प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तो न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और इसे केवल सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, न कि केवल कानूनी बिंदु बनाने पर।

48. यहां तक कि अगर वहाँ एनआईटी के स्पष्ट शर्तों से एक मामूली विचलन किया गया था, यह एक असफल बोलीदाता.¹² के इशारे पर निविदा को अलग सेट करने के लिए अदालतों के लिए दुर्भावनापूर्ण के अभाव में अपने आप में पर्याप्त नहीं हो जे फिर से शुरू करने के बीच की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा। न केवल इस तरह के समान संचार ने सभी बोलीदाताओं को एक समान पायदान पर रखा, बल्कि कोई नहीं था, ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की संभावना। जब यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है कि उन्होंने सोचा था कि नीलामी शाम 7:35 बजे बंद हो जाएगी और इसलिए उन्हें जल्दी बंद होने पर आश्चर्य हुआ, और न ही उन्होंने वास्तव में फिर से शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की व्याख्या पर प्रकाश डाला या आपत्ति जताई, सवाल विवादास्पद है और इस पर एक निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए।

¹¹ (2016) 16 एस सी सी 233

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य बनाम अमर देव प्रभा एवं अन्य।

49. समय विस्तार की मात्रा से संबंधित प्रश्नों में उद्यम करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि सीआई-इंडिया द्वारा सभी को एक ही संदेश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि नीलामी प्रक्रिया को दोपहर 1:03 बजे नीलामी बंद होने और दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू करने के बीच की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा। न केवल इस तरह के समान संचार ने सभी बोलीदाताओं को एक समान पायदान पर रखा, बल्कि कोई ईमेल के स्पष्ट शब्दों को देखते हुए किसी भी भ्रम की संभावना। जब यह प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं है कि उन्होंने सोचा था कि नीलामी शाम 7:35 बजे बंद हो जाएगी और इसलिए उन्हें जल्दी बंद होने पर आश्चर्य हुआ, और न ही उन्होंने वास्तव में फिर से शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की व्याख्या पर प्रकाश डाला या आपत्ति जताई, सवाल विवादास्पद है और इस पर एक निष्कर्ष नहीं दिया जाना चाहिए।

50. इसके अतिरिक्त, हम पहले प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिट दाखिल करने में देरी के औचित्य में योग्यता भी नहीं देखते हैं। यह दावा किया जाता है कि कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नंबर 6 28 दिनों की अवधि के भीतर गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहा। हालांकि, हम यह नहीं देखते हैं कि यह एएमआर-देव प्रभा को नीलामी की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देने, या प्रतिवादी नंबर 6 और अपीलकर्ता के बीच अनुबंध की गोपनीयता के स्थापित कानूनी सिद्धांत को दूर करने की अनुमति कैसे देगा

(III) प्राधिकरण की व्याख्या का सम्मान

51. अंत में, हम एक और मूलभूत समस्या से निपटने के लिए इसे आवश्यक समझते हैं। यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 केवल एनआईटी की शर्तों को लागू करना चाहता है। इस तरह के अभ्यास में निहित संविदात्मक शर्तों की व्याख्या है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वाणिज्य के क्षेत्र में अनुबंधों की न्यायिक व्याख्या विधियों की व्याख्या करते समय एक अलग पायदान पर है।

52. वर्तमान तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि बीसीसीएल और सी1-इंडिया ने एनआईटी के खंडों का सहारा लिया है, चाहे वह प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में प्रतिवादी नंबर 6 की देरी की माफी को सही ठहराने के लिए हो या तकनीकी विफलता के

आधार पर नीलामी फिर से शुरू करने का उनका निर्णय। बीसीसीएल ने इन दस्तावेजों को लिखा है, उनकी आवश्यकताओं की सराहना करने और उनकी व्याख्या करने के लिए बेहतर स्थिति में है।¹³

53. उच्च न्यायालय को इस समझ को स्थगित कर देना चाहिए था, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से विकृत या दुर्भावनापूर्ण न हो। यह देखते हुए कि इन खंडों की बीसीसीएल की व्याख्या कैसे प्रशंसनीय थी और बेतुकी नहीं थी, केवल संविदात्मक व्याख्या की राय में मतभेद उच्च न्यायालय के लिए इस निष्कर्ष पर आने का आधार नहीं होना चाहिए था कि अपीलकर्ता ने अवैधता की है।

निष्कर्ष

54. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा दायर अपील के साथ-साथ मैसर्स आरके ट्रांसपोर्ट और मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनुमति है। नतीजतन, एएमआर-देव प्रभा द्वारा दायर अपील खारिज कर दी जाती है। उच्च न्यायालय की खंड पीठके 12.04.2018 के फैसले को रद्द किया जाता है और एएमआर-देव प्रभा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।

¹³ अफकोनस आधारभूत संरचना लिमिटेड बनाम नागपूर रेल मेट्रो निगम लिमिटेड , (2016) 16 एस सी सी 818